

देशबन्धु

जबलपुर, गुरुवार 10 सितम्बर 2026

वर्ष - 70

अंक - 287

पृष्ठ - 12

मूल्य - 3.00 रु.

■ नस्लीय नफरत का...
■ असलियत से ज्यादा...

04

■ जिस चीन पर पाकिस्तान को था भरोसा उसी...
■ सबसे ज्यादा सैलरी वाले प्रधानमंत्री कौन हैं...

09

■ पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से...
■ बेंट कूड 100 डॉलर के पार

11

■ भारतीय टीम ऑलम्पिक...
■ रिवलाब की ओर ईस्ट...

10

सागर संक्षेप

तीस से अधिक बच्चों की मौत के बाद जागा प्रशासन

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर, देशबन्धु। बालाघाट जिले में संक्रामक बीमारियों के कारण तीस से अधिक बच्चों की मौत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। याचिकाकर्ता ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद हलफनामे के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूमिया तथा जस्टिस प्रदीप मिश्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर आगामी सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की गयी है। गौरतलब है कि नरसिंहपुर निवासी अंशुल तिवारी की तरफ से समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर बालाघाट में संक्रामक बीमारियों के कारण तीस से अधिक बच्चों की मौत के संबंध में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि बच्चों को पर्याप्त उपचार नहीं मिल रहा है। 50 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल में करीब 400 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। अधिवक्ता अभिषेक पांडे, अधिवक्ता अतुल शुक्ला ने सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था।

पुणे में पेपर लीक विवाद के बीच छात्र ने की आत्महत्या

पुणे। पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पेपर लीक की बार-बार हो रही घटनाओं और आर्थिक तंगी के कारण उसने यह कदम उठाया। मृतक की पहचान प्रथमेश देशमुख के तौर पर हुई है। पुलिस को शक है कि गंभीर आर्थिक परेशानियों, जिसमें 2.5 लाख रुपये का बकाया कर्ज भी शामिल है, के कारण उसने यह कठोर कदम उठाया।



चूहा-सुनती हो- रोक के बाद भी छात्र को नोटिस भेजने पर सीजेआई बोले- मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत कैसे हुई ?

चुहिया- हां प्रिये- इन दिनों 'पालिका' चाहे जो हो, हिम्मत तो सत्ता बल से ही आती है।

मोदी कैबिनेट के अहम फैसले

रेलवे के सात हाई-डेंसिटी कॉरिडोर होंगे फोर-ट्रैक

नई दिल्ली, देशबन्धु। केंद्र सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण पर लगातार जोर दे रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि- आज की बैठक में रेलवे आधुनिकीकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। ये परियोजनाएं पिछले 12 वर्षों से चल रहे रेलवे के व्यापक बदलाव और आधुनिकीकरण के काम का हिस्सा हैं। वैष्णव ने बताया कि-सात हाई-डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर को फोर-ट्रैक करने की योजना है। इन कॉरिडोर पर ट्रैक क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में इन मार्गों पर बढ़ने वाले यातायात का दबाव संभाला जा सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के हाई-डेंसिटी कॉरिडोर को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता और कोलकाता-दिल्ली मार्ग मिलकर गोलंडन क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली-चेन्नई और मुंबई-कोलकाता इसके दो डायगोनल हैं।

इसके अलावा दिल्ली-गुवाहाटी कॉरिडोर भी इस योजना में शामिल है। इस तरह कुल सात हाई-डेंसिटी कॉरिडोर को चार-लेन किया जा रहा है। वैष्णव के मुताबिक, इन सभी परियोजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। फिलहाल करीब 4,000 किलोमीटर के हिस्से के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

3-मल्टी ट्रेकिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी

कैबिनेट समिति ने बुधवार को रेलवे मंत्रालय की तीन मल्टी-ट्रेकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 10,783 करोड़ रुपये है। इनके पूरा होने के बाद रेलवे के नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। इन रेल मार्गों पर होगा काम-मंजूर की गई परियोजनाओं में खड़गपुर-झारसुगड़ा के बीच चौथी लाइन और कटनी-पेंडा रोड सेक्शन में चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। इसके अलावा बिलासपुर (उसलापुर)-पेंडा रोड सेक्शन में तीसरी लाइन बनाई जाएगी। सरकार के मुताबिक, अतिरिक्त रेल लाइन बनने से इन मार्गों की क्षमता बढ़ेगी। इससे ट्रेनों की आवृत्ति बेहतर होने के साथ परिचालन दक्षता और सेवा की विश्वसनीयता में सुधार होगा। मल्टी-ट्रेकिंग से रेलवे परिचालन को सुचारु बनाने और भीड़भाड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने बताया कि इन परियोजनाओं



◆ कई रुटों पर बढ़ेगी क्षमता
◆ गोलंडन क्वाड्रिलेटरल और उसके दोनों डायगोनल पर बढ़ेगी क्षमता

की योजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है। इसका फोकस मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को बेहतर बनाने पर है। इसके लिए एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श को आधार बनाया गया है।

पांच राज्यों के 14 जिलों को मिलेगा फायदा ?

ये तीनों परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छग के 14 जिलों से होकर गुजरेंगी। परियोजनाओं के जरिए भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सरकार के अनुसार, इससे लगभग 4,790 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं रेलमंत्री का माना आभार

भोपाल, देशबन्धु। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिलों को लाभान्वित करने वाली 3 मल्टी-ट्रेकिंग रेल परियोजनाओं की सोगात के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं रेल मंत्री श्री वैष्णव का हृदय से आभार व्यक्त किया है।

सागर पहुंचे मुख्यमंत्री, जहरीली शराब से पीड़ितों के हाल जाने

निर्देश- जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाए

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि-सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब से लोगों की हुई मृत्यु के प्रकरण में कठोरतापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाए। जिले में नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने मृतकों के प्रति अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज सागर के बुन्देलखंड मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में जनप्रतिनिधियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन अपराध और असामाजिक गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने



◆ लोगों की मृत्यु पर व्यक्त किया शोक
◆ पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की हुई संयुक्त बैठक
◆ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से नशा मुक्ति अभियान चलाने कहा

अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले के साथ-साथ आस-पास और सीमावर्ती क्षेत्रों में गहन जांच अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा जहाँ कहीं भी शंका या संदिग्ध गतिविधि की गुंजाइश हो, वहाँ तत्परता से पड़ताल की जाए और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से नशा मुक्ति अभियान जनसहयोग से चलाने कहा है।

अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो

मुख्यमंत्री ने शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से सोशल मीडिया या अन्य विभिन्न माध्यमों पर अनावश्यक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखने और उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

दुबई में मध्यप्रदेश को 53 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले

◆ दुबई के निवेशकों को भारा मध्यप्रदेश
◆ मध्यप्रदेश की निवेश क्षमता से रुबरु हुआ वैश्विक उद्योग जगत



भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 6 से 8 सितंबर का दुबई दौरा मध्यप्रदेश की निवेश रणनीति को वैश्विक मंच पर नए विस्तार देने वाला रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशा निवेश के साथ तकनीक, बाजार, निर्यात और रोजगार को जोड़कर मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश एवं विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है।

एआईएम कांग्रेस-2026 में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश को केवल निवेश के गंतव्य के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक कंपनियों और निवेशकों के लिए दीर्घकालिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया। दुबई प्रवास के दौरान लगभग 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यूएई के शीर्ष

मंत्रियों, तालारस्तान के नेतृत्व, विश्व बैंक और डीपी वर्ल्ड, क्रिसेंट एंटरप्राइज़, जेम्स एजुकेशन, शराफ ग्रुप, चोइथराम्स, राणा होल्डिंग्स, वीएफएस ग्लोबल और BEEAH जैसी कंपनियों के साथ हुई बैठकों में

करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने, विमानन संपर्क बढ़ाने तथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में उच्चस्तरीय निवेशक दल के साथ भागीदारी की दिशा में सहमति जताई, वहीं विश्व बैंक ने एआई और डिजिटल गवर्नेंस परियोजनाओं

मुख्यमंत्री ने दुनिया के उद्योग जगत को दिया म.प्र. आने का न्योता

लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, एआई एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, ई-मोबिलिटी, फार्मा, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, आधुनिक विनिर्माण और वेस्ट-टू-एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी की संभावनाएं खुलीं। दुबई ने मध्यप्रदेश में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र का अध्ययन

में सहयोग में रुचि दिखाई। डीपी वर्ल्ड और शराफ ग्रुप के साथ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, BEEAH के साथ कचरा प्रबंधन एवं वेस्ट-टू-एनर्जी, GEMS के साथ एजुकेशन और कौशल विकास तथा चोइथराम्स के साथ रिटेल और फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं ने दौरे को ठोस कारोबारी अवसरों से जोड़ा।

छात्र को नोटिस पर भड़के सीजेआई

बोले- मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत कैसे हुई ?

नई दिल्ली, देशबन्धु। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। प्रशासन ने कानून की पढ़ाई कर रहे एक 20 साल के छात्र को 'सरकार-विरोधी प्रचार' फैलाने और दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए साथी छात्रों को उसकासे के आरोप में प्रिवेंटिव नोटिस (एहतियाती नोटिस) जारी किया था।

कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनों में शामिल होने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद कोई भी एजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि- जब सीनियर वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने बेंच का ध्यान गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के छात्र अक्षत त्रिपाठी को 4 सितंबर को जारी किए गए नोटिस की ओर दिलाया, तो कोर्ट गौतम बुद्ध नगर जिले और एजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इस बारे में जवाब मांगा। सीजेआई ने कहा- कोई मजिस्ट्रेट नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हमने साफ़ कर दिया था कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी! कोई भी मजिस्ट्रेट उस आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। सीजेआई ने भट्टाचार्य की इस बात से सहमति जताई कि नोटिस जारी करना-भले ही उसे अगले दिन वापस ले लिया गया हो-प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश का उल्लंघन था। सीजेआई ने कहा, 'हमारे स्पष्ट और साफ़ आदेश को देखते हुए किसी युवा के खिलाफ़ कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता।



80 साल की बुजुर्ग बोलैं- शौर्य चक्र वापस ले लो

बेटे की शहादत के 22 साल बाद भी नहीं दिया गया प्लॉट

नई दिल्ली। वतन के लिए जान फिदा करने वाले वीरों के परिवारों को अगर घोषणा के बाद भी समुचित राहत न दी जाए, या देने में बहुत देर कर दी जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? इन्हीं परिस्थितियों में लखनऊ की रहने वाली 80 वर्षीय की सावित्री सक्सेना ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि या तो उनके बलिदान हुए बेटे को लेकर किए गए वादों को पूरा किया जाए, या फिर मरणोपरांत मिला 'शौर्य चक्र' और अन्य सम्मान वापस ले लिए जाएं।

सावित्री सक्सेना के छोटे बेटे, असिस्टेंट कमांडेंट विवेक सक्सेना 8 जनवरी 2003 को मणिपुर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए बलिदान हो गए थे। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार 'शौर्य चक्र' और 'राष्ट्रपति पुलिस पदक' से सम्मानित किया गया था। विवेक सक्सेना के बलिदानी होने का बाद सरकार की तरफ से परिवार को जमीन और एक स्मारक बनवाने जैसी कई सहायता देने का वादा किया गया था। लेकिन 22 साल बीत जाने के



बाद भी परिवार दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर थक चुका है, और वादे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। ऐसे में परिवार का आरोप है कि उन्हें बार-बार यह साबित करने के लिए कहा गया कि वे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं। जबकि वे सालों से लखनऊ में ही रहे, यहीं पढ़ाई की, और शहीद बेटे की याद से जुड़ी चीजें भी यहीं एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद हैं।

आर्थिक सम्मान मिलने में भी लग गए 21 साल- इतना ही नहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि शौर्य

अधिकारी पूछ रहे अजीबोगरीब सवाल

हद तो तब हो गई जब अधिकारियों ने यह तक पूछ लिया कि शादी से पहले मां कहाँ रहती थीं। परिवार का सवाल है कि जिस पते पर सरकार ने सालों पहले खुद 75000 रुपये का चेक भेजा था, उसी पते पर आज उनकी नागरिकता पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?

चक्र के साथ मिलने वाली मौद्रिक सहायता परिवार को साल 2024 में जाकर मिली। यानी बेटे की शहादत के पूरे 21 साल बाद। फाइलें अलग-अलग विभागों के चक्कर काटती रहीं और अधिकारी बार-बार वैरिफिकेशन के नाम पर लटकाते रहे। बलिदानी असिस्टेंट कमांडेंट विवेक सक्सेना की मां बताती हैं कि उनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है। इस उम्र में सरकारी दफ्तरों के धक्के खाना उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कष्टदायक हो गया है। उनका कहना है कि अब उनमें और भागदौड़ करने की ताकत नहीं बची है।

दो साल से तैयार फूड लैब, अब एनएबीएल की रिपोर्ट का इंतजार

8-9 अगस्त को हो चुका निरीक्षण, रिपोर्ट आने के बाद तय होगी मान्यता



देशबन्धु फॉलोअप

जबलपुर, देशबन्धु। करीब दो साल से तैयार खड़ी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की लगभग 5 करोड़ रुपये लागत वाली अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब अब एनएबीएल की अंतिम रिपोर्ट के इंतजार में है। लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दिलाने की प्रक्रिया के तहत 8 और 9 अगस्त को एनएबीएल की टीम द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। अब विभाग को निरीक्षण रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट में यदि निर्धारित तकनीकी मापदंडों पर लैब को उपयुक्त पाया जाता है तो इसके बाद मान्यता मिलने का रास्ता साफ होगा।

लैब में आधुनिक जांच उपकरण और आवश्यक

आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद अब तक यहाँ नियमित रूप से खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच शुरू नहीं हो सकी है। मुख्य वजह एनएबीएल की मान्यता का लंबित रहना है। यही कारण है कि जबलपुर सहित महाकौशल क्षेत्र से लिए जाने वाले खाद्य नमूनों को परीक्षण के लिए अभी भी भोपाल भेजने की व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में आपत्ति हुई तो फिर बढ़ सकता है इंतजार

सूत्रों के मुताबिक एनएबीएल की रिपोर्ट इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कड़ी है। निरीक्षण के दौरान यदि किसी तकनीकी या व्यवस्थागत कमी की ओर इशारा किया जाता है तो विभाग को उसे दूर करना होगा। वहीं, यदि रिपोर्ट संतोषजनक रहती है तो मान्यता मिलने के बाद लैब में खाद्य नमूनों की जांच शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

दो साल से इंतजार, अब रिपोर्ट पर टिकी उम्मीद
करीब दो वर्ष पहले स्थापित इस लैब को लेकर विभागीय स्तर पर लंबे समय से तैयारियां चल रही थीं। एनएबीएल निरीक्षण से पहले उपकरणों के कैलिब्रेशन, आवश्यक दस्तावेज, तकनीकी मानकों और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। इसके बाद अगस्त में एनएबीएल टीम ने दो दिन तक लैब का निरीक्षण किया। अब निरीक्षण के दौरान सामने आए बिंदुओं और टीम की रिपोर्ट का इंतजार है।

- फैक्ट फाइल**
- लागत: लगभग 5 करोड़ रुपये
 - लैब: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग
 - एनएबीएल निरीक्षण: 8 और 9 अगस्त
 - वर्तमान स्थिति: निरीक्षण रिपोर्ट का इंतजार
 - मान्यता के बाद: खाद्य नमूनों की जांच शुरू
 - लंबित अवधि: दो वर्ष से जांच नहीं

महाकौशल को मिलेगा सीधा फायदा
मान्यता मिलने के बाद जबलपुर में ही खाद्य पदार्थों की वैज्ञानिक जांच संभव हो सकेगी। इससे नमूनों को भोपाल भेजने की जरूरत कम होगी और रिपोर्ट मिलने में लगने वाला समय भी घटेगा। खाद्य मिलावट के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिहाज से भी यह सुविधा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मेड़ाघाट में 24 - 25 अक्टूबर को आयोजित होगा दो दिवसीय नर्मदा महोत्सव

तैयारियों को लेकर लोक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

जबलपुर, देशबन्धु। लोक निर्माण मंत्री राकेश निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार एवं जिला सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत, भाजपा में शरद पूर्णिमा पर भेड़ाघाट में इस वर्ष आयोजित किये जाने वाले नर्मदा महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक में महोत्सव के लिए कलाकारों के चयन, प्रचार-प्रसार, सुरक्षा, यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में सांसद आशीष दुबे, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक सुशील तिवारी 'इंद्र', जेडीए अध्यक्ष संदीप जैन, नगर निगम अध्यक्ष रिकूज विज, नगर परिषद अध्यक्ष भेड़ाघाट चतुर सिंह लोधी, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, नगर

निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार एवं जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत, भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजकुमार पटेल, भाजपा युवा मोर्चा ग्रामीण जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में शरद पूर्णिमा को 24 एवं 25 अक्टूबर को भेड़ाघाट में आयोजित किये जाने वाले नर्मदा महोत्सव की रूपरेखा पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि महोत्सव में भजन, सूफी, शास्त्रीय एवं सेमी-क्लासिकल संगीत को प्राथमिकता दी जाए और कलाकारों को कार्यक्रम की प्रकृति के बारे में पहले से जानकारी दी जाए।



नचिकेता महाविद्यालय में एनएसएस सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

जबलपुर, देशबन्धु। नचिकेता महाविद्यालय विजयनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रादुविच से समन्वयक डॉ. शोभाराम मेहरा एवं एनएसएस मुक्त इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. देवांशु गौतम मुख्य अतिथि व सदस्य के रूप से उपस्थित रहे। साथ ही ग्राम सूबा के सरपंच डॉ. रितेश सिंह एवं जिला अस्पताल से डॉ. वैशाली खन्ना उपस्थिति रही। सलाहकार समिति की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. प्रीति रेखा चंद्रा के साथ समिति सदस्य के रूप में रजिस्ट्रार आर.एस. चंदेल तथा कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रज्ञा दुबे व राहुल बोहरे आदि उपस्थित रहे।

पीसीसीएम ने किया मैहर सीमेंट प्लांट की रेल कनेक्टिविटी देखी

जबलपुर, देशबन्धु। पश्चिम मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक अरविंद कुमार रजक द्वारा बुधवार को मैहर रेलवे स्टेशन, मालगोदाम एवं क्षेत्र में स्थित विभिन्न रेल आधारित वाणिज्यिक सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य यात्री सुविधाओं में सुधार, माल परिवहन को बढ़ावा देना तथा रेलवे एवं व्यापारिक हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। इस दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, जबलपुर शशांक गुप्ता

भी उपस्थित थे। मैहर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे विकास एवं पुनर्विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मैहर मालगोदाम में व्यापारियों एवं हितधारकों के साथ बैठक कर माल परिवहन से संबंधित समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों पर चर्चा की गई। केजेएस सीमेंट प्लांट के अधिकारियों के साथ रेलवे साइडिंग की कनेक्टिविटी एवं रेल परिवहन को सुगम बनाने के संबंध में चर्चा की गई।



दो अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निरस्त

जबलपुर, देशबन्धु। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर दो अनुज्ञप्ति धारियों के स्वीकृत शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये हैं। इन अनुज्ञप्तिधारियों में थाना मझौली के अंतर्गत ग्राम अनघोरा निवासी राहुल सिंह यादव तथा पाटन थाना के अंतर्गत चौधरी मोहल्ला पाटन निवासी कृष्णानंद उर्फ कृष्ण प्रसाद बेहुरे शामिल हैं। दोनों अनुज्ञप्ति धारियों की लायसेंस बंदूक से हथ्या के प्रकरण संबंधित थानों में पंजीबद्ध है। कलेक्टर द्वारा शस्त्र लायसेंस निरस्त करने की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के अनुशांसा पर की गई है।

सर्पदंश से मासूम की मौत मामले में फिर उठे सवाल, डॉक्टर को हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग

जबलपुर, देशबन्धु। कटंगी में पिछले महीने सर्पदंश से दो वर्षीय मासूम की मौत के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के आशीष मिश्रा ने बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम एडीएम को जापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच करने और कटंगी अस्पताल के डॉक्टर महापदाश तथा डॉ. आदर्श बिश्नोई को हटाने की मांग की है। जापन में आरोप लगाया गया है कि सर्पदंश के बाद मासूम को तत्काल शासकीय अस्पताल कटंगी ले जाया गया था, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया। परिजनों के अनुसार, मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस समय अस्पताल प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि सर्पदंश के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां और इंजेक्शन उपलब्ध थे। डॉक्टर आदर्श बिश्नोई के अनुसार, घटना के समय



अस्पताल में प्रसव का मामला चल रहा था, जिसके कारण नर्स तत्काल बच्चे का उपचार नहीं कर पाई। उनका कहना था कि यदि बच्चे को समय पर उपचार मिल जाता तो उसके बचने की संभावना थी, लेकिन उस समय मौके पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। अब समाजवादी पार्टी ने इसी मामले को लेकर प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है। जापन में संबंधित डॉक्टरों को हटाने के साथ ही जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की मांग की गई है।

गंदगी से बजबजा रहे पॉथ एरिया के फुटपाथ

कई-कई दिनों तक नहीं उठ रहा कचरा



जबलपुर, देशबन्धु। शहर की कई बस्तियों, गली और मोहल्लों में तो बुरी तरह कचरे से बजबजा ही रहे हैं लेकिन अब पॉथ इलाके भी गंदगी से अछूते नहीं रह गए हैं। जिसका अंदाजा नेपियर टाउन-राइट टाउन जैसे इलाकों के फुटपाथों को देखकर लगाया जा सकता है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के आसपास के फुटपाथों की हालत तो बिल्कुल ऐसी हो गई तो उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना कठिन हो जाता है कि वे फुटपाथ हैं कि कोई अस्थायी कचरा घर।

फेंका जा रहा मेडिकल वेस्ट
नेपियर टाउन, राइट टाउन में रहने वाले कुछ लोगों ने बताया कि एक तो फुटपाथ पर पड़ा कचरा कई-कई दिन तक नहीं उठाया जाता ऊपर से जो कसर बाकी रह जाती है, उसे कुछ हॉस्पिटल संचालक पूरा कर देते हैं। कुछ वाशिंगें का कहना है कि फुटपाथों पर जहां भी कचरे के ढेर लगे हैं, वहां एक साथ तो नहीं लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है।



बैठकी वसूली भी चल रही
अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए कुछ लोग इन फुटपाथों पर दुकानें भी लगाते हैं। जिनसे बकायदा नगर निगम का बाजार विभाग बैठकी वसूली भी करता है। लेकिन गंदगी के बीच दुकान लगाने वाले लोगों को सुविधाएं धेलाभर भी नहीं मिल रही हैं। ऐसे में आधे फुटपाथ पर जहां दुकानें लग रही हैं और आधा गंदगी से बजबजा रहा है तो पैदल चलने वालों को समझ नहीं आ रहा है कि वे निकलें तो निकलें कहां से। अब हालात ये हैं कि दुकानदारों को मजबूरी में गंदगी के बीच पेट भरने के लिये दुकान चलानी पड़ रही है।

महापौर-निगमायुक्त सहित पूरी टीम को बधाई देते हुए बोले राकेश सिंह वायु सर्वेक्षण में पुरस्कार प्रत्येक नागरिक का सम्मान



जबलपुर, देशबन्धु। राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संस्कारधानी ने देश के मानचित्र पर अपनी एक अलग और ऐतिहासिक पहचान दर्ज कराई है। इस प्रतियोगिता में देश भर में तीसरा स्थान हासिल करने की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बुधवार को महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू', निगम अध्यक्ष रिकू विज एवं नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार को शुभकामनाएं दीं। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य

सार-समाचार

तीन दिन तक जलापूर्ति रहेगी बाधित सुधारा जा रहा मदार छल्ला पानी की टंकी का लीकेज

जबलपुर, देशबन्धु। मदार छल्ला टंकी से जुड़े क्षेत्रों में कल से तीन दिन तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। कार्यपालन यंत्री जल कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि नर्मदा जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 55 एमएलडी ललपुर जल शोधन संयंत्र से जुड़ी मदार छल्ला उच्चस्तरिय पानी की टंकी के लीकेज हेतु ग्राउंटिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुधार कार्य के कारण आज 10 सितम्बर की सुबह लेकर 12 सितंबर की शाम तक जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। सुधार कार्य के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को होने वाली असुविधा के लिए महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू', जल प्रभारी दामोदर सोनी और निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने खेद व्यक्त किया है। प्रभावित क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी।



लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के गुरुवार के कार्यक्रम

जबलपुर, देशबन्धु। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह गुरुवार 10 सितम्बर को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लोक निर्माण मंत्री गुरुवार की सुबह 11.30 बजे भक्ति धाम गौरीघाट में नर्मदा मंडल की मंडल कार्य समिति, दोपहर 12.30 बजे सुपाताल स्थित होटल शी-रॉक में रानी दुर्गावती मंडल की मंडल कार्य समिति, दोपहर 2 बजे त्रिपुरी चौक के समीप मारुति मंडप में महाराणा प्रताप मंडल की मंडल कार्य समिति तथा दोपहर 3.30 बजे विधायक कार्यालय मदन महल में गिरिराज किशोर कपूर मंडल की मंडल कार्य समिति को बैठक में शामिल होंगे।



फाइनल में नवीन (आरपीएफ) ने जयवीर (उ.रे) को 10-00 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जयवीर ने रजत पदक तथा शिसराम गुर्जर (प.रे) ने कांस्य पदक प्राप्त किया। 74 किग्रा भार वर्ग फाइनल में नवीन (उ.रे) ने ऋषि (रेलवे सुरक्षा विशेष बल) को चित कर स्वर्ण पदक जीता। ऋषि ने रजत पदक तथा राजू यादव (उ.पूरे) ने कांस्य पदक हासिल किया।

राम मंदिर चंदा चोरी के विरोध में पुतला फूँका

जबलपुर, देशबन्धु। अयोध्या राम मंदिर में दान के करोड़ों रूपए गायब होने के बाद देशभर में इसकी निंदा हो रही है। वहीं शहर में कांग्रेस ने आधारताल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गुहमंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय का पुतला फूँका। कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता चमन पासी के नेतृत्व में किये इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने बड़े चोरों को बचा लिया और छोटे चोरों को जेल भेज दिया। अरबों रूपए के चंदे की बंदरबांट हो गई। प्रदर्शन के दौरान, मनोज भदौरिया, जगू आशिक, इकबाल ताहिर अली, डॉ. नीरज शर्मा, डॉ. प्रमोद लाल, पूरन कोरी, सोहन कटार, एड. इफान मंसूरी, गंगा ठाकुर, बबलू तिवारी, सुबोध पहाड़िया, राजू तोमर, बीजू तिवारी, संतोष लोधी, विकास विश्वकर्मा, कीर्ति सिंह, बाबा लहरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।



अधिक से अधिक करदाताओं को करें लाभान्वित : निगमायुक्त

लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा करते हुए दिए निर्देश

जबलपुर, देशबन्धु। करदाताओं और पात्र हितग्राहियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने राजस्व वसूली अभियान के साथ-साथ प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने 12 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का लाभ करदाताओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक करदाताओं को प्रेरित किया जाए ताकि वे अपने लंबित संपत्तिकर, जलकर और अन्य बकाया देयों का निपटारा कर शासन द्वारा दी जा रही छूट व सुविधाओं का लाभ ले सकें। इस पहल से जहां एक ओर करदाताओं को सरचार्ज से राहत मिलेगी, वहीं निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी। निगमायुक्त ने पीएम स्वनिधि, संबल योजना, स्ट्रीट वेंडर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक संबल देने वाली इन योजनाओं के तहत आवेदनों के त्वरित निराकरण और पात्र हितग्राहियों तक सीधे लाभ पहुंचाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने अमृत एवं सीवर परियोजना की भी समीक्षा की। उन्होंने



शहर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए अमृत योजना और सीवर नेटवर्क के कार्यों को समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने पर जोर दिया। बैठक में अपर आयुक्त, अधीक्षण यंत्री, उपायुक्त, सहायक आयुक्त और समस्त विभागीय प्रमुख मौजूद थे।

21 बार बजेगा वादे का ऑडियो, भाजपा से पूछेंगे कब जिला बनेगा सिहोरा?

विधायक को स्मरण पत्र सौंप
आंदोलन के प्रथम चरण का समापन
2 अक्टूबर को भाजपा संभागीय कार्यालय के सामने होगा प्रदर्शन

सिहोरा, देशबन्धु। चुनावी मंच से किया गया वादा अब भाजपा के लिए सवाल बनता जा रहा है। सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति ने आंदोलन का पहला चरण पूरा करते हुए बुधवार को विधायक संतोष बरकड़े को स्मरण पत्र सौंपने की अपनी घोषणा पूरी की। विधायक के बाहर रहने पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर अनुपम सराफ से पत्र लिया। समिति ने इसके साथ ही आंदोलन के अगले चरण का ऐलान कर दिया।

समिति ने 2 सितंबर से सिहोरा के जिम्मेदार भाजपा नेताओं को स्मरण पत्र सौंपकर उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी द्वारा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सिहोरा जिला बनाने को लेकर की गई घोषणा का ऑडियो सुनाया।

समिति ने नेताओं से सवाल किया कि जब चुनाव के समय जनता के बीच मंच से सिहोरा जिला बनाने की बात कही गई थी, तो सत्ता में



आने के बाद उस घोषणा पर कार्रवाई क्यों दिखाई नहीं दे रही?

समिति के सदस्यों ने कहा कि स्मृति ईरानी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता द्वारा किया गया प्रस्ताव सत्ता की चक्काचौंध में भुला देना उचित नहीं है। भाजपा को भविष्य में फिर जनता के सामने चुनाव में जाना है और उस समय जनता अपने वादों का हिसाब जरूर मांगेगी।

पहले आग्रह, अब आंदोलन
समिति का कहना है कि सिहोरा जिला की मांग को लेकर जिम्मेदार नेताओं से पहले भी कई बार आग्रह किया जा चुका है, लेकिन सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। इसलिए अब समिति

केवल आश्वासन के भरोसे रुकने वाली नहीं है।

समिति ने साफ कर दिया है—अब बात आग्रह से आगे बढ़कर जवाबदेही तक जाएगी।आंदोलन के अगले चरण में 2 अक्टूबर को जबलपुर स्थित भाजपा संभागीय कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रदर्शन के दौरान स्मृति ईरानी की चुनाव पूर्व घोषणा का ऑडियो 21 बार बजाते हुए प्रश्न उठाएगी कि सिहोरा की जनता से चुनाव पूर्व किया गया वादा कब पूरा होगा?स्मृति ईरानी की घोषणा पर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की?सिहोरा को जिला बनाने की पहल आखिर किस स्तर पर अटकती है? ‘

विधायक के सामने रखे दो विकल्प
विधायक संतोष बरकड़े के नाम स्मरण पत्र सौंपते समय समिति ने उनके समक्ष दो प्रस्ताव रखे।

पहला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के समक्ष विधायक सिहोरा द्वारा सिहोरा जिला बनाने का लिखित अध्यावेदन प्रस्तुत किया जाए और आयोग के सामने सिहोरा का मजबूत पक्ष रखा जाए। दूसरा यह कि विधायक स्वयं भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी को साथ लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात करें और चुनाव पूर्व की गई घोषणा को अमल में लाने की मांग करें।

अब निगाहें 2 अक्टूबर पर हैं जब भाजपा के संभागीय कार्यालय के सामने 21 बार चुनावी वादे की आवाज गुंजेगी और भाजपा नेतृत्व से एक ही सवाल पूछा जाएगा— ‘सिहोरा जिला कब?’

बुधवार को स्मरण पत्र सौंपने वालों में समिति के अनिल जैन, कृष्ण कुमार कुररिया,रामजी शुक्ला,संतोष पांडे,शरद सेठ,प्रदीप दुबे,पुरषोत्तम गुप्ता,मोहन सोंधिया,राजेश कुररिया,सुमित शुक्ला,अलोक जैन,जितेंद्र श्रीवास,दशरथ पटेल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

किसी को दुखी कर कोई सुखी नहीं हो सकता : मुनिश्री निर्दोष सागर



दुनिया में आदि अनंत काल से दुख देने वाले को दुख ही मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा परसों मिलेगा आने वाले समय में कभी भी मिलेगा जो बोया है इस ही काटना पड़ेगा लेकिन निश्चित ही मिलेगा यह संसार का नियम है इसलिए अगर सांसारिक प्राणी को सुख की कामना करना है तो उसे दूसरे को दुख देकर सुख पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये मांगलिक प्रवचन के दौरान पूज्य आचार्य संत शिरोमणि श्री 108 विद्यासागर महाराज जी के परम शिष्य पूज्य मुनि निर्दोष सागर महाराज जी ने आज अपनी प्रवचन के दौरान श्री शांतिनाथ जिनालय बड़े जैन मंदिर प्रांगण में भक्त जनो के समक्ष कही।

उन्होंने यह भी कहा कि आप अपनी बात बोले लेकिन ऐसी बोले कि जो दूसरे को कारण प्रिया हो क्योंकि आपके मुख से निकले वचन आपको सम्मान भी दिला सकते हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को नोपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और सोच समझकर सुनकर अपने शब्दों को बोलना चाहिए।

सार-सामाचार



बिजली बिल बकायादारों के विरुद्ध हुई कार्रवाई

गोसलपुर, देशबन्धु। सिहोरा डिवीजन अंतर्गत बिजली बिल वसूली के लिए 8 अगस्त को सघन अभियान चलाया गया। संभाग के बड़े एवं लम्बे से समय से भुगतान न करने वाले बकायादारों को पूर्व में भुगतान के लिए नोटिस जारी किए गए थे, जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान न किए जाने पर अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में कार्यपालन अभियंता एवं संभाग के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता द्वारा टीम बनाकर अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गोसलपुर खितौला, इंदाना, मझौली एवं मझगवां में बकायादारों के कुल 95 कनेक्शन विच्छेदित किए गए।

गोसलपुर वितरण केंद्र के अंतर्गत सहायक अभियंता यशवंत चौधरी एवं कनिष्ठ अभियंता रमेश सिन्हा के दल द्वारा ग्राम सिलुआ में लंबे समय से भुगतान न करने पर 2 उपभोक्ताओं की मोटर साइकिल जब्त की गई। इसी प्रकार खितौला अंतर्गत सहायक राकेश गढ़वाल एवं सहायक अभियंता वीरेंद्र उडके के दल ने मोटर पम्प एवं अन्य सामग्री जब्त की। मझगवा वितरण केंद्र के अंतर्गत डीआरए प्रकिया के तहत उपभोक्ताओं की पेशी संपन्न की गई, जिसमें कुल 20 उपभोक्ताओं ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा एवं बकाया राशि का भुगतान कराया अभियान में कुल 114 उपभोक्ताओं द्वारा 8.5 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया।

ग्रामीण क्षेत्रों के गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, अब मात्र 25 दिन में रिफिल होगा सिलेंडर

गोसलपुर, देशबन्धु। क्षेत्र के घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। संस्कार गैस एजेंसी गोसलपुर के संचालक अनिल कुमार जैन ने जानकारी दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर बुकिंग की समयवधि को काफी कम कर दिया गया है।

अब ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरेलू उपभोक्ता 45 दिन के बजाय हर 25 दिन में अपना गैस सिलेंडर रिफिल बुक कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। बुकिंग की नई अवधि अब 45 दिन की जगह केवल 25 दिन में सिलेंडर की बुकिंग होगी। गोसलपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। बताया गया कि यह नियम तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है। एजेंसी के संचालक अनिल कुमार जैन ने बताया की एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और लंबित रिफिल मामलों में आई कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है इस बदलाव से ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर मिल सकेगा और उन्हें लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

जुझारी में इनामी दंगल आज

गोसलपुर, देशबन्धु। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी घुल्हाई अमावस्या के पावन अवसर पर गोसलपुर के समीप जुझारी में विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया जा रहा है दंगल का आयोजन आज गुरुवार को ग्राम के अखाड़ा परिसर में दोपहर 2 बजे से होगा। आयोजन समिति के राजा दुबे ने बताया की इस दंगल में जबलपुर कटनी नरसिंहपुर उमरिया अनूपपुर, शहडोल मंडला सहित छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र यूपी के नामी पहलवान अपना दमखम दिखाते आएंगे। विजेता पहलवानों के लिए आकर्षक नकद ईनाम रखा गया है। क्षेत्रीय जनपद सदस्य अनिल चौधरी ने कहा कि जुझारी का यह दंगल क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है यह सिर्फ कुश्ती नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और भाईचारे का प्रतीक है। इस अवसर पर विधायक संतोष बरखड़े सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे।

शोक संतुप्त परिवार से मिले विधायक बरकड़े

गोसलपुर, देशबन्धु। गत दिवस कछपुरा निवासी नोखे लाल पटेल और गोसलपुर निवासी अनुपम जैन रानू के निधन पश्चात शोक संतप्त परिवार से मिलने क्षुब्ध विधायक संतोष बरकड़े पहुंचे उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में परिवार को ढांडस बंधाया। विधायक श्री बरकड़े ने शोकाकुल परिवार के साथ कुछ समय बिताया परिजनों की बात सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा दुख की इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं विधायक के इस आत्मीय दौरें से शोक संतप्त परिवार को संबल मिला इस अवसर पर उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।

गोसलपुर क्षेत्र की पंचायतों में लटके रहते हैं ताले

गोसलपुर, देशबन्धु। गोसलपुर अंचल की ग्राम पंचायतों में इन दिनों अव्यवस्था का आलम है। अधिकांश पंचायत भवनों में सुबह से शाम तक ताले लटके रहते हैं सचिव समय पर गांव नहीं पहुंचते कई-कई दिन तक सचिवों के दर्शन तक नहीं होते जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

हितग्राही परेशान, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा- स्थानीय ग्रामीणों ने बताया की वे पंचायत के चक्कर काट रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, समग्र ई-केवाईसी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पीएम आवास और राशन कार्ड से संबंधित कार्यों के लिए हितग्राहियों को रोज

मुख्यालय पर न रहकर

कर रहे हैं खानापूर्ति

ग्रामीणों का आरोप है की सचिव मुख्यालय पर न रहकर मुख्यालय से बाहर निवास कर रहे हैं और कभी-कभार आकर खानापूर्ति कर चले जाते हैं। पंचायत के रोजगार सहायक भी मनमानी कर रहे हैं।

शासन के आदेशों की उड़

रही धज्जियां –उल्लेखनीय है

कि शासन और जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में भी कई बार स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके हैं कि

सभी सचिव नियमित रूप से पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे और पंचायत भवन निर्धारित समय पर खुले रहेंगे, इसके बावजूद आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। वही दूसरी ओर जनपद सीईओ औचक निरीक्षण नहीं करती है। शासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

कलेक्टर से शिकायत की तैयारी–जनसेवा समिति के विजय दुबे कमल पटेल इकाश पटेल और ग्रामवासियों ने निर्णय लिया है की शिकायत कलेक्टर जबलपुर जिला पंचायत सीईओ से की जाएगी। ग्रामीणों ने मांग की है की पंचायतों को प्रतिदिन समय पर खोला जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर कार्रवाई की मांग, सौपा ज्ञापन



सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि शराब का अवैध कारोबार जारी रहने से युवा वर्ग पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संगठन ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए, जहां अवैध रूप से शराब का भंडारण अथवा बिक्री किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की आवश्यकता है।

15 वर्ष जमे रहने के बाद भी नहीं छूटा मलाईदार कुर्सी का मोह!

तबादला नीति की उड़ रही धज्जियां, कृषि एसडीओ की लंबे समय से पाटन में पदस्थापना पर उठे सवाल

पाटन, देशबन्धु। शासन की तबादला नीति में जिम्मेदार पदों पर अधिकारियों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापना पर रोक के बावजूद कृषि विभाग में पाटन ब्लॉक की कृषि एसडीओ की कथित तौर पर 15 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि स्थायी नियुक्ति से पूर्व भी उन्होंने कुछ वर्षों तक संविदा पर पाटन में सेवाएं दी थीं। यदि यह जानकारी सही है तो पाटन में उनकी कुल सेवा अवधि और भी अधिक बढ़ जाती है।

तबादला नीति पर उठ रहे सवाल–बताया जा रहा है कि हाल ही में एसडीओ का कृषि विभाग में प्रमोशन भी हुआ है, इसके बावजूद पाटन की एसडीओ कृषि की जिम्मेदारी से उन्हें हटया नहीं गया। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ रहने को लेकर किसान संगठनों और स्थानीय लोगों में बहुत नाराजगी है। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को सामान्यतः एक ही स्थान पर लंबे समय तक पदस्थ रखने से प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

खाद-बीज और कीटनाशक दुकानों से सांठगांठ का लगाया आरोप–स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि लंबे समय से

स्तर पर फर्जी किरायानामा तैयार कर वर्षों से हेडक्वार्टर अलाउंस लेने तथा जबलपुर में बैठकर ही सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज कराने के आरोप भी सामने आए हैं। इन आरोपों की विभागीय जांच कराई जाना आवश्यक है,ताकि तथ्य और स्पष्ट हो सकें।

कर्मचारी के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला भी चर्चा में–कृषि विभाग में पदस्थ एक ड्राइवर कर्मचारी के साथ लंबे समय से कथित शोषण एवं अपमानजनक व्यवहार के आरोप भी पूर्व में सामने आ चुके हैं। बताया जाता है कि पदस्थापना से जुड़े मामले को लेकर उक्त कर्मचारी न्यायालय की शरण में गया था और वहां से उक्त कर्मचारी को राहत भी मिली थी। आरोप है कि न्यायालय के निर्देशों के बावजूद कर्मचारी से ड्राइवर के स्थान पर चपरासी का कार्य कराया जा रहा है। इस पूरे मामले में न्यायालय के आदेशों एवं विभागीय रिकॉर्ड की जांच से स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

किसान संगठन भोपाल में करेंगे शिकायत राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा कृषि एसडीओ की लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापना सहित खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण व्यवस्था



इस व्यस्त मार्ग से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है।

बड़े हादसे से पहले जागे प्रशासन–स्थानीय ग्रामीणों और नियमित यात्रियों ने जिला प्रशासन तथा संबंधित निर्माण एजेंसी से मांग की है कि जब तक नए पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक इस पुराने पुल पर तत्काल मजबूत रिपरिंग, मजबूत बैरिकेडिंग, रेडियम संकेतक और दोनों ओर सुरक्षा दीवारें बनाई जाएं, ताकि किसी भी संभावित बड़ी जनहानि को टाला जा सके।

किसानों को लंबे समय से पाटन में पदस्थापना पर उठे सवाल

तथा अन्य कथित अनियमितताओं को लेकर भोपाल में संबंधित विभागीय अधिकारियों के समक्ष शिकायत करने की तैयारी की जा रही है। किसान संगठन का कहना है कि पाटन ब्लॉक में खाद एवं कृषि सामग्री की दुकानों का सघन एवं निष्पक्ष औचक निरीक्षण कराया जाए,ताकि किसानों को निर्धारित गुणवत्ता एवं उचित दर पर कृषि सामग्री उपलब्ध हो सके।

जिले से बाहर स्थानांतरण की किसानों ने की मांग–किसानों एवं स्थानीय लोगों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि एसडीओ की लंबे समय से चली आ रही पाटन पदस्थापना की उच्चस्तरीय जांच कर उन्हें तत्काल जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाए। लोगों का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापना बनी हुई है।

किसानों का कहना है कि यदि शासन तबादला नीति, हेडक्वार्टर अलाउंस, सार्थक एप पर दर्ज उपस्थिति, न्यायालयीन आदेशों के पालन तथा खाद-बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं से कथित संबंधों की निष्पक्ष जांच कराए तो कई तथ्यों का खुलासा हो सकता है। अब देखना यह है कि शासन और कृषि विभाग इन गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है।

जिस चीन पर पाकिस्तान को था भरोसा, उसी ने बना ली दूरी, इस मोहभंग की वजह क्या?

ट्रंप और पुतिन के बीच एक घंटे तक टेलीफोन पर हुई बातचीत, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?



इस्लामाबाद। पाकिस्तान की बिजली कंपनी के निजीकरण की दौड़ से चीनी कंपनी बाहर हो गई है। चीन की कंपनी के इस कदम को पाकिस्तान के पावर सेक्टर में चीनी दिलचस्पी से जोड़कर देखा जा रहा है। जानें पूरा मामला और इसकी वजह। पाकिस्तान की बिजली कंपनी पर चीन की नजर थी, फिर क्या हुआ? डील के अगले चरण से चीनी कंपनी बाहर पाकिस्तान और चीन की करीबी दोस्ती जगजाहिर है। लेकिन अब इसमें दरार पड़ती नजर आ रही है। चीन ने पाकिस्तान के बिजली क्षेत्र अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल चीन की एक कंपनी पाकिस्तान की बड़ी बिजली वितरण कंपनी फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी के निजीकरण की दौड़ से बाहर हो गई है। जो कंपनी बाहर हुई

है वह चीन की सरकारी कंपनी पावरचाइना की एक सहायक कंपनी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब पाकिस्तान अपनी सरकारी बिजली वितरण कंपनियों में निजी निवेश लाने की कोशिश कर रहा है। निक्की एशिया ने इस घटनाक्रम को पाकिस्तान के पावर सेक्टर में चीन की घटती दिलचस्पी के संकेत के तौर पर देखा है।

फैसको की डील में क्या हुआ?– पाकिस्तान सरकार ने फैसको के निजीकरण के लिए घरेलू और विदेशी निवेशकों से रुचि पत्र यान ई मांगे थे। सरकार 51 से 100 फीसदी तक हिस्सेदारी के साथ कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल निजी निवेशकों को देने की योजना पर काम कर रही है। फैसको के लिए कुल 12 निवेशकों ने ईओआई जमा किए थे। इनमें तीन कंपनियां तुर्किये की, एक चीन की और आठ पाकिस्तानी निवेशक या समूह शामिल थे। चीनी पक्ष के तौर पर जियांगशी इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन ने रुचि दिखाई थी। यह पाँवर चाइनासमूह से जुड़ी कंपनी है।

शुरुआत में यह चीन की भागीदारी पाकिस्तान के बिजली वितरण क्षेत्र में एक अहम कदम मानी जा रही थी। लेकिन अगस्त के अंत में तस्वीर बदल गई। पाकिस्तान की निजीकरण आयोग बोर्ड ने फैसको के लिए 10 कंपनियों को प्री-क्वालिफाई किया, जबकि जियांगशी इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन उनमें शामिल नहीं थी।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को करीब एक घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब अमेरिका रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहा है। दोनों नेताओं के बीच चर्चा में यूक्रेन युद्ध और हाल में अमेरिकी अधिकारियों की माँस्को व कीव यात्रा प्रमुख मुद्दे रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव वित्कोफ और जेरेड कुशनर ने हाल में माँस्को और कीव का दौरा किया था। इन यात्राओं को ट्रंप प्रशासन की रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौते की दिशा में नई पहल के तौर पर देखा जा रहा है। क्रैमलिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने बातचीत को बेहद साफ और खुली चर्चा बताया। उन्होंने कहा कि पुतिन और ट्रंप ने अमेरिकी दूतों की यात्राओं के नतीजों पर अपने विचार साझा किए। पुतिन ने ट्रंप को यूक्रेन के मोर्चे पर मौजूदा हालात के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि युद्ध को जल्द समाप्त कराने में अमेरिका की ओर से वास्तव में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। रूस लगातार युद्ध के मैदान में अपनी स्थिति को मजबूत बताता रहा है। माँस्को का दावा है कि उसकी सेना विभिन्न मोर्चों पर आगे बढ़ रही है और युद्ध में उसके सैन्य लक्ष्य अब भी पहले की तरह काममें हैं।



ट्रंप-पुतिन के बीच किन मुद्दों पर हुई बात- फोन पर हुई बातचीत के दौरान पुतिन ने यूरोप को लेकर रूस की स्थिति भी स्पष्ट की। उशाकोव के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप से कहा कि रूस की यूरोपीय देशों के खिलाफ कोई आक्रामक योजना नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब यूरोपीय देशों में रूस की संभावित गतिविधियों और यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ कथित तोड़फोड़ अभियान को लेकर चिंता बनी हुई है। माँस्को ने इन आरोपों को खारिज किया है। रूस लंबे समय से यूरोप और पश्चिमी देशों के उन

आरोपों को खारिज करता रहा है, जिनमें उस पर पड़ोसी देशों और नाटो सदस्यों के खिलाफ भविष्य में सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई जाती है। इस बीच, अमेरिका और रूस के बीच उच्चस्तरीय संपर्क बढ़ने से यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। अगस्त के अंत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख जॉन रैटक्लिफ ने भी माँस्को का अचानक दौरा किया था। उन्होंने रूस को किसी नाटो सदस्य देश पर हमला नहीं करने की चेतावनी दी थी।

सुडोकू					7388			
	2	5			8			6
		8			2			
	6		3		7			5
	9							7
		3		4		6		
1							9	
5			8		3		6	
			1			7		
4			9			5	1	

: नियम :

- कुल 81 (9×9) वर्ग हैं, जिसमें 9 (3×3) वर्गों का एक खंड (ब्लॉक) बनता है।
- हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते हैं।
- बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कॉलम,कतार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

हल आज ही के अंक में

वर्ग पहेली

7388

१	२			३		४	
			५				
६				७			८
			९				
१०		११			१२		
			१३				
१४	१५			१६	१७		
			१८	१९			
२०				२१			२२
	२३						

बायें से दायें:–

- कम पढ़ा-लिखा, कट्टर अक्षर पूजक, मुल्ला या मौलबी
- पहाड़ के नीचे की भूमि
- पति (उर्दू)
- विवाह विच्छेद (उर्दू)
- वैधों को मिलने वाली एक उपाधि
- दिखलाना
- गुथ्थी, फंसाव, या किसी समस्या का दूर होना
- कमल
- जिसके पास कोई हथियार न हो नि:शस्त्र १४. नशे में अंड-बंड बोलना पथभ्रष्ट होना १६. झुका हुआ १८. जिसमें मन न लगे, अरुचिकर (उर्दू)
- सरस्वती, दुर्गा
- किसी भाषा के अक्षरों की क्रमबद्ध सूची
- ऐतिहासिक इमारत

ऊपर से नीचे:–

- हथेली
- मुल्लती, जिसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई हो
- आवयव में आना, कुद्ध होना
- क्रांतिल
- क्रय करना, मोल लेना (उर्दू)
- पेचीदगी, कठिनाता, घुमावदार होना
- संधि, मेल, समझौता
- टूट कर गिरना, (पेड़ से पत्ते या सिर के बालों का) बरसना
- उठना, उठाना, बढ़ती, उन्नति
- ममता रहित, निष्ठुरता
- ताकतवर
- वर देने वाला
- अनुवाद (उर्दू)
- पत्नी (उर्दू)
- नया, नवीन
- मुंह से निकलने वाला लसदार तरल पदार्थ

वर्ग पहेली-7387

१	२		३		४	
ब	ही	खा	ता		अ	प
						वि
र		छा	अ	ट्ट	ट	ज
६					७	८
सा	कि	न	तु		क	ला
						ध
त		लि				
			सा	य	ल	क
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
ब	का	सु	र		रो	च
						क
	का		धा	सं	बं	ध
						ल
१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
भ	या	तु	र	ग्रा	क	पा
						ल
ग		ला		क	म	ल
						दु
२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
द	रिं	दा	दा		ल	का
						र
इ		२३	२४	२५	२६	२७
		न	र	पि	शा	च
						व

युसूफ कुरैशी, मो. 8109948408

सबसे ज्यादा सैलरी वाले प्रधानमंत्री कौन हैं, हर महीने मिलते हैं इतने करोड़ रुपये



सिंगापुर के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की सैलरी में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। खास बात है कि इससे पहले ही यहां के मंत्री सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सरकारी अधिकारियों की सूची में शामिल थे। जानिए अब उन्हें हर महीने कितने रुपये मिलेंगे। सिंगापुर के मंत्रियों के वेतन में 15 साल बाद बढ़ोतरी की गई है। वे पहले ही दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंगे ने मंगलवार को कहा कि अगर वेतन में बदलाव नहीं किया गया तो राजनीति में शीर्ष

प्रतिभाओं को आकर्षित करना मुश्किल होगा। इसके अलावा पीएम की सैलरी में भी इजाफा हुआ है। वोंगे ने संसद में कहा कि संशोधित वेतन ढांचे के तहत सबसे निचले स्तर के मंत्री का वार्षिक वेतन 11 लाख सिंगापुर डॉलर (करीब 8.68 लाख अमेरिकी डॉलर) से बढ़ाकर 18 लाख सिंगापुर डॉलर (करीब 14.2 लाख अमेरिकी डॉलर) किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए निर्धारित वेतन 22 लाख सिंगापुर डॉलर (करीब 17 लाख अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर 36 लाख सिंगापुर डॉलर (करीब 28 लाख अमेरिकी डॉलर) हो जाएगा। इसके अलावा अन्य सांसदों के भत्तों में भी वृद्धि की जाएगी।

कितना वेतन मिलेगा- प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सबसे निचले स्तर के अधिकतर मंत्री मौजूदा

कार्यकाल के अंत तक करीब 13.5 लाख सिंगापुर डॉलर अर्जित कर सकेंगे। इसके बाद वेतन 18 लाख सिंगापुर डॉलर के मानक तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि प्रदर्शन और जिम्मेदारियों के आधार पर तय किया जाएगा। वोंगे ने यह नहीं बताया कि उनका नया वेतन कितना होगा। हालांकि, नौ प्रतिशत समायोजन के बाद उनका वेतन करीब 24 लाख सिंगापुर डॉलर (करीब 18.9 लाख अमेरिकी डॉलर) हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह अगले पांच वर्षों तक वेतन वृद्धि की पूरी राशि दान कर देंगे। सिंगापुर में राजनीतिक पदों पर मिलने वाला वेतन एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि मंत्रियों का वेतन आम नागरिकों की तुलना में काफी अधिक है। सरकार ने इस व्यवस्था को बचाव करते हुए कहा कि यह निजी क्षेत्र और सार्वजनिक सेवाओं से सक्षम लोगों को

राजनीति में लाने तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाए रखने के लिए जरूरी है। देंगे दान वोंगे ने कहा है कि वह बढ़ी हुई पूरी सैलरी को अच्छे कामों के लिए दान दे देंगे। उन्होंने कहा, राजनीति में सैलरी मुश्किल और भावनात्मक मुद्दा है। वोंगे की पीपुल्स एक्शन पार्टी का सिंगापुर संसद में दबदबा है। खास बात है कि इस इजाफे के पहले भी वह कई नेताओं से ज्यादा वेतन हासिल कर रहे थे। इसमें अमेरिका और जी 7 देशों के अन्य नेता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, %इसमें शामिल रकम ज्यादातर नागरिकों की कमाई से कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सिंगापुर के लोग इसकी बारीकी से जांच पड़ताल क्यों करते हैं और क्यों बहुत से लोग इस मामले को लेकर इतनी मजबूत राय रखते हैं।

भाषण के बीच चीन ने थमाई पर्ची, फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने मंच से पढ़कर कर दिया बेनकाब!

दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय डिफेंस समिट के दौरान उस समय बड़ी नाटकीय स्थिति पैदा हो गई, जब फिलिपींस के रक्षा मंत्री गिलबर्टो सी. तेओदोरो को भाषण देते समय अचानक चीन का एक नोट थमा दिया गया। इस नोट में दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के रुख और दावों का ब्योरा दिया गया था। मंच पर ही चीनी दूतावास के अधिकारियों की इस अजीब हरकत से भड़के फिलिपींस के

रक्षा मंत्री ने खुले मंच से चीन के इरादों पर सवाल उठाए और उस पर धौंस जमाने, गुंडागर्दी करने और आक्रामकता दिखाने का सीधा आरोप जड़ा। **क्या है पूरा मामला?**– दरअसल इंटरनेशनल डिफेंस फोरम पर जब तेओदोरो अपने संबोधन में क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर बोल रहे थे, तभी चीन के प्रतिनिधिमंडल के फोरम पर जब तेओदोरो अपने संबोधन में क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर बोल रहे थे, तभी चीन के प्रतिनिधिमंडल के

क्या रुख है इसके बारे में लिखा था। तेओदोरो ने तुरंत सबके सामने उस नोट के बारे में बताते हुए कहा कि एक खूले और लोकतांत्रिक मंच पर इस तरह दबाव बनाने की कोशिश चीन के घटिया रवैये को दर्शाती है। फिलिपींस के रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना अवैध और एकराफा मालिकाना हक जमाना चाहता है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों और यूपन के समुद्री कानून का खुला उल्लंघन है।

दक्षिण चीन सागर में क्यों बढ़ा है तनाव?– पिछले कुछ महीनों में फिलिपींस और चीन के कोस्ट गार्ड जहाजों के बीच दक्षिण चीन सागर के विवादित सेकंड थॉमस शोल और स्कारबोरो शोल के पास कई बार खतरनाक टकराव हुआ है। चीनी जहाजों की तरफ से फिलिपींस की री-सप्लाय बोट पर वाटर कैनन चलाने, लेजर लाइट से अंधा करने और टक्कर मारने की कई घटनाएं सामने आई हैं।

कवायद

जम्मू-कश्मीर में केंद्र की पीएम सूर्य सरोवर योजना को लगे पंख

मानसब और मानसर में फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं की तैयारी

■ जम्मू, (देशबन्धु)। जम्मू-कश्मीर ने केंद्र की पीएम सूर्य सरोवर योजना के तहत फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के विकास के लिए कश्मीर में मानसबल झील और जम्मू डिवीजन में मानसर झील को चुना है, और व्यवहार्यता मूल्यांकन और आवश्यक अनुमतिवों की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। जम्मू-कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी (जेकेडीए) के एक अधिकारी ने बताया कि इस पहल में झीलों और

जलविद्युत परियोजना जलाशयों सहित उपयुक्त अंतर्देशीय जल निकायों का उपयोग करके तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने परिकल्पना की गई है। अधिकारी के बकौल, जम्मू-कश्मीर से अब तक दो जल निकायों को चुना गया है-कश्मीर में मानसबल और जम्मू मंडल में मानसर। व्यवहार्यता अध्ययन और अनुमति प्रक्रिया फिलहाल जारी है। संबंधित वितरण कंपनियों (डीआईएसकोम) की सहमति प्राप्त होने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिसके बाद चयनित जल

■ डीआईएसकोम की सहमति प्राप्त होने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जिसके बाद चयनित जल निकायों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा

■ 2026 तक प्रदेश में लगाए गए 38 हजार 955 सौर पैनल

निकायों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। उनका कहना था कि डिस्कॉम को पहले अपनी सहमति देनी होगी। एक बार सहमति मिल जाने के बाद, सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके अनुसार परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। इस पहल के तहत, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए जल सतहों का उपयोग करने

के विकल्प के रूप में फ्लोटिंग सोलर तकनीक पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता नहीं होगी। यह दृष्टिकोण उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकता है जहां बड़े पैमाने पर सौर

www.deshbandhump.com

जबलपुर | भोपाल | सागर | सतना | रायपुर | बिलासपुर | नई दिल्ली

स्कूल वैन के चके के नीचे आया मासूम, मौके पर मौत

अचानक गेट खुलने से गिरा छात्र, वैन चालक गिरफ्तार

कटनी, देशबन्धु। प्रदेश में स्कूल वैन में टूंस-टूंसकर बच्चों को ले जाया जा रहा है। छोटे-छोटे से मासूम इस तरह पढ़ने जाने के लिये मजबूर हैं। लेकिन क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर स्कूल ले जाना अब खतरनाक हो गया है। कबाड़ वाहनों हो चुके वाहनों से भी बच्चों को स्कूल लाया ले जाया जा रहा है। जिसके कारण कटनी जिले के विजयराघोगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। स्कूल वैन का गेट अचानक खुल जाने के कारण एक 10 साल का मासूम गिर गया और पहिये की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद स्कूल वैन के रखरखाव पर भी सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची विजयराघवगढ़ थाना पुलिस ने स्कूल वैन जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, विजयराघवगढ़ निवासी दिनेश यादव का 10 वर्षीय बेटा जीत यादव दूसरी कक्षा में पढ़ता था। रोज की तरह बुधवार को वह स्कूल जाने के लिए वैन में सवार हुआ था। इसी दौरान चलती



वैन का गेट अचानक खुल गया, जिससे जीत नीचे गिर गया और वैन का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक आनन-फानन में बच्चे को विजयराघवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा, लेकिन उसे अस्पताल में छोड़कर मौके से भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद जीत को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया।

बसों की जांच, वैन अछूती

वहीं प्रदेशभर की स्कूलों की बसों की जांच की गई। लेकिन वैनों में जांच के नाम पर सिर्फ गैस किट ही निकलवाई गई। इनके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद लगातार बसों पर ही प्रशासन ने ध्यान दिया। अब इस घटना के बाद परिवहन विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रदेशभर में वैन से बच्चों को स्कूल भेजने वाले अभिभावकों को भी डर सताने लगा है।

इनका कहना है-

कटनी के विजयराघोगढ़ में हुई घटना अत्यंत दुखद है। जिले के कई बच्चे वैन से स्कूल जाते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि स्कूली बसों और वैन के रखरखाव के संबंध में जानकारी लें। इसलिये समय-समय अभियान चलाकर वाहनों की चैकिंग चलाई जाएगी। अभिभावकों को भी सतर्कता बरतनी चाहिये।

-श्रीमती रिकू शर्मा, आरटीओ

11 सितंबर से नया मौसमी तंत्र होगा सक्रिय

12 तारीख से फिर भारी बारिश के आसार

जबलपुर, देशबन्धु। मध्यप्रदेश शांत रहेगा। 11 सितंबर को में तेज बारिश को दौर धम गया पश्चिम-मध्य और उत्तर- है। अब केवल खंडवर्षा ही देखने को मिल रही है। जबलपुर में पिछले कुछ दिनों से बारिश गायब है। यहां खंडवर्षा दर्ज की जा रही है। दिन तेज धूप निकली तो वहीं कुछ इलाकों में अलग-अलग समय पर खंडवर्षा हुई। जिससे उमस ने जोर पकड़ लिया। जबलपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि जिले के विभिन्न स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने, झंझावात और झोकेदार तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं।

मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 सितंबर तक अधिकांश इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत



पश्चिम बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के संकेत हैं। इसके असर से 12 सितंबर से मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 12 सितंबर को छतरपुर, पन्ना, दमोह और कटनी में भारी बारिश हो सकती है। नए मौसमी तंत्र के आगे बढ़ने के साथ प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर बढ़ा असंतोष, प्रदेशभर में बहिष्कार की तैयारी

जबलपुर, देशबन्धु। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। विभाग परीक्षा को इसी वर्ष 31 दिसंबर से पहले कराने की तैयारी में जुटा है, वहीं जबलपुर संभाग में शिक्षक संगठनों ने परीक्षा की अनिवार्यता और पात्रता के मानदंड स्पष्ट किए बिना किसी भी प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया है। संभाग के शिक्षकों के बीच इस मुद्दे को लेकर बैठकों और आपसी चर्चा का दौर तेज हो गया है। संगठनों का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों

को दोबारा पात्रता परीक्षा के दायरे में लाना व्यावहारिक और न्यायसंगत नहीं है।

जबलपुर संभाग में फैसले का इंतजार- जबलपुर संभाग के जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और डिंडोरी जिलों में शिक्षक इस मामले में विभाग के लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी और किन्हें इससे छूट मिलेगी। फिलहाल स्पष्ट आदेश सामने नहीं आने से शिक्षकों के बीच अलग-अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। संगठनों ने संकेत दिया है कि नियम स्पष्ट

होने के बाद ही संभाग स्तर पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जबलपुर में शिक्षक संगठनों की सक्रियता इस पूरे मामले को महत्वपूर्ण बना रही है। यहां संगठन पदाधिकारी लगातार शिक्षकों से संपर्क कर रहे हैं और परीक्षा के विरोध में एकजुटता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर एक और महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा एजेंसी का है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ऑफलाइन माध्यम से इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित करने में असमर्थता जताए जाने के बाद विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करना पड़ रहा है।

प्रदेश में इंटरन डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, स्टाइपेंड 50 प्रतिशत बढ़ा, अब मिलेंगे 21500

जबलपुर/भोपाल, देशबन्धु। भोपाल में आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों पर पुलिसिया रवैये के विरोध तथा मासिक भत्ते में इजाफे की मांग को लेकर बुधवार को जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने कामबंद हड़ताल कर दी। प्रदर्शनकारी चिकित्सकों ने ओपीडी कक्षों का पूर्ण बहिष्कार किया, जिसके चलते संभागभर से पहुंचे सैकड़ों मरीजों को पर्वी बनवाने से लेकर परामर्श तक भारी अव्यवस्था झेलनी पड़ी। जूनियर डाक्टरों का आरोप है कि वे कठिन परिस्थितियों में लगातार ड्यूटी देने के बावजूद शासन उनकी बुनियादी मांगों की उपेक्षा कर रहा है। राजधानी में साथी डॉक्टरों के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम ने इस रोष को और भड़का दिया है, जिससे



संपूर्ण विंध्य-महाकौशल अंचल की शासकीय स्वास्थ्य प्रणाली पर गहरा संकट मंडराने लगा है। प्रांतीय स्तर पर उन्हें वर्तमान में महज 14,300 रुपए का अल्प मासिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेशभर के डॉक्टरों ने कामबंद हड़ताल कर दी। लेकिन शम होते तक सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा और स्टाइपेंड बढ़ाने की घोषणा

विद्युतीकरण को मिली रफ्तार

1,763 स्कूलों में काम पूरा

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 2,752 स्कूलों का किया था सर्वे

जबलपुर, देशबन्धु। विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य बहुत तेजी से कराया जा रहा है। जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले 24 जिलों के ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई तेज गति से की जा रही है, जहां बिजली का आभाव था। जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त 2026 तक की स्थिति के विद्युत वितरण कंपनी ने राज्य शिक्षा केंद्र के चिन्हित 2,752 गैर-विद्युतीकृत विद्यालयों का सर्वेक्षण किया है। सर्वे के दौरान 394 विद्यालयों में पहले से विद्युत कनेक्शन पाए गए। साथ



ही यह तथ्य भी सामने आया कि कुछ विद्यालयों में भवन उपलब्ध ना होने और अन्य कारणों के चलते तत्काल कनेक्शन संभव नहीं है। शेष 2,254 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।

ऐसे समझें पूरी स्थिति

जानकारी के मुताबिक सर्वे के दौरान 814 विद्यालय ऐसे मिले हैं, जहां बिना किसी अतिरिक्त विस्तार कार्य के सीधे विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा सकते हैं, जबकि 1,440 विद्यालयों में विद्युत लाइन/नेटवर्क विस्तार की आवश्यकता पाई गई है। कंपनी द्वारा इन दोनों श्रेणियों में कार्य को गति देते हुए अब तक कुल 1,763 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इनमें बिना विस्तार कार्य वाले 814 विद्यालय तथा विस्तार कार्य पूर्ण कर 949 विद्यालयों को विद्युत सेवा से जोड़ा जा चुका है।

जबलपुर-गया के बीच 3-3 फेरा चलेगी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन

जबलपुर, देशबन्धु। पितृपक्ष के अवसर पर गया में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी संख्या 01701/01702 जबलपुर-गया-जबलपुर पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन को 3-3 ट्रिप चालाने का निर्णय लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों के लिए 10 सितम्बर से कंप्यूटीकृत आरक्षण केन्द्रों एवं ऑनलाइन आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से आरक्षण कराया जा सकता है।

रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गाड़ी संख्या 01702 गया-जबलपुर एक्सप्रेस स्पेशल 28 सितम्बर, 3 एवं 8 अक्टूबर को गया स्टेशन से दोपहर 15:30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी-ऑन-सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित



दीन दयाल उपाध्याय, मिर्जापुर, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, मैहर, कटनी एवं सिहोरा रोड होते हुए सुबह 8:10 बजे जबलपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 01701 जबलपुर-गया एक्सप्रेस स्पेशल 29 सितम्बर, 4 एवं 9 अक्टूबर को जबलपुर स्टेशन से रात्रि 21:25 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड होते हुए दोपहर 14:30 बजे गया पहुंचेगी।

एंबुलेंस न मिलने से 2 घंटे तड़पती रही महिला, मौत 5 महीने में 8वीं प्रसूता ने तोड़ा दम

कटनी, देशबन्धु। कटनी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के कारण एक और गर्भवती महिला की जान चली गई। दीमरखेड़ा तहसील के खमरिया गांव की 24 साल की गुलाब बाई कोल ने अस्पताल की दहलीज पर दम तोड़ दिया। पति मोहन कोल ने बताया कि नौ महीने की गर्भवती पत्नी को तेज प्रसव पीड़ा होने पर 108 जननी एक्सप्रेस को फोन किया गया था। कॉल सेंटर से बार-बार आश्वासन मिलता रहा, लेकिन दो घंटे बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची। मजबूर होकर परिजन किराए की गाड़ी से खमतरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।



गए। जब तक परिजन महिला को डिलीवरी वाई तक ले जा पाते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामले में कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने जांच कराने और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

फाइलों में 17, सड़क पर 7 एंबुलेंस- कटनी जिले में आपातकालीन सेवाओं का बुरा हाल है। कागजों में जिले के लिए 17 जननी एंबुलेंस आवंटित हैं, लेकिन सड़क पर सिर्फ 7 गाड़ियां ही चल रही हैं। बाकी 10 वाहनों का कोई अंता-पता नहीं है।

FOR PRIVATE SCREENING CALL
+91799968989
FOR ONLINE BOOKING & OFFER
BOOK FROM

BOOKMYSHOW
CALL BOOKING 0761-4069888, 4069889

BOOK YOUR TICKET & FOOD NO WhatsApp
SAMDREYACINEMA+917999968989

HANUMAN ANSH
TUESDAY OFFER
₹119 Flat
All Day All Show

MIRZAPUR
₹149 Flat

HANUMAN ANSH
9:00AM 09:30AM 12:00PM
11:30PM 02:45PM 04:15PM
15:30PM 07:15PM 08:30PM
10:15PM 11:30PM

MIRZAPUR
09:20AM 10:00AM 12:30PM
03:00PM 06:30PM 08:00PM
10:30PM 11:30PM

MAHAPRABHU
JAGANNATH
01:00PM

समूह सिनेमा

सोनू पोल्की

बड़ा ब्रॉयलर - ₹. 102

मीडियम ब्रॉयलर - ₹. 130

छोटा ब्रॉयलर - ₹. 142

मो. - 9039925999

J.B.F.A

जबलपुर ब्रॉयलर फार्मर्स एसोसियेशन

मुर्गा छोटा - ₹. 146

मुर्गा मीडियम - ₹. 134

मुर्गा बड़ा - ₹. 106

मुर्गा जम्बो - ₹. 106

मो. 9039925000, 9425800409

शहडोल, देशबन्धु। जिले के सीधी थाना क्षेत्र के छत्ता गांव में जादू-टोने के शक में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 60 वर्षीय महिला की कथित तौर पर गला घोटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में मृतका की जेठानी को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी को शक था कि मृतका उसके घर पर जादू-टोना करती है, जिससे उसकी बेटी की तबीयत खराब रहती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था।

जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार सुबह की है। मृतका सुखरनिया सिंह गोंड अपने घर के पास मवेशियों को चारा

खिला रही थीं। इसी दौरान उनकी जेठानी मुन्नी बाई वहां पहुंची। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। आरोप है कि विवाद के दौरान मुन्नी बाई ने

गला घोटकर उतारा मौत के घाट

चुनरी से सुखरनिया का गला घोट दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही सीधी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के लोगों से

पूछताछ की और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी मुन्नी बाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के पीछे की वजह और घटना के पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। बेटी की बीमारी को लेकर था जादू-टोने का शक पुलिस के अनुसार, मुन्नी बाई की बेटी अक्सर बीमार रहती थी। उसे संदेह था कि सुखरनिया उसके घर पर जादू-टोना करती हैं, जिसकी वजह से बेटी की तबीयत खराब रहती है। इसी शक को लेकर दोनों महिलाओं के बीच पहले भी विवाद हुआ था। पुलिस फिलहाल इसी विवाद को हत्या की वजह मानकर जांच कर रही है।

www.deshbandhu.co.in

जबलपुर | भोपाल | सागर | सतना | रायपुर | बिलासपुर | नई दिल्ली

CMYK